GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

The Hindu Important News Articles & Editorial For UPSC CSE

Wednesday, 05 Feb, 2025

Edition : International Table of Contents

Page 01 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	अमेरिका ने 200 भारतीयों को सैन्य विमान से वापस भेजा
Page 01 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	चीन ने अमेरिका पर माल टैरिफ लगाकर पलटवार किया, गूगल की जांच की
Page 08 **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	भारत-इंडोनेशिया संबंध वैश्विक संबंधों के लिए एक मार्गदर्शक हैं
Page 10 **Syllabus : GS 3 : भारतीय अर्थव्यवस्था**	कर कटौती एकतरफा जुआ क्यों है?
समाचार में	'विकसित भारत' लक्ष्य के लिए किस तरह की नौकरियों की जरूरत है
Page 08 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का बाहर होना वैश्विक स्वास्थ्य को नया आकार देने का मौका है

GEO IAS It's about quality

Page 01 : GS 2 : International Relations

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित अमेरिका यात्रा से कुछ दिन पहले, डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन ने अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

U.S. sends back 200 Indians on military plane

New Delhi said to have confirmed nationality of all individuals before they were boarded on the plane; moves comes a week after Prime Minister Narendra Modi spoke with U.S. President Donald Trump on phone and days before an expected meeting between them; new U.S. administration puts the number of illegal Indian immigrants at 18,000

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

Days before Prime Minister Narendra Modi's expected visit to the U.S., the Donald Trump administration has started the process of deporting illegal Indian immigrants.

Sources confirmed that a wide-bodied military aircraft took off from the U.S. early on Tuesday morning carrying around 200 Indian nationals. Official sources here said that the Indian side confirmed the nationality of all the individuals before the U.S. authorities went ahead with the deportation.

Mr. Modi had spoken to President Donald Trump last week following which the White House announced that the Prime Minister was expected to visit Washington DC in February. "We will work together for the welfare of our people and towards global peace, prosperity, and security," Mr. Modi said after the telephone conversation.

Shortly thereafter, Mr. Trump addressed the issue of illegal immigration from several countries, including India, and said, "He [Mr. Modi] will do what's right when it comes to taking back illegal Indian immigrants from America."

The conversation was held against the backdrop of reports that the two sides were in discussion over the presence of at least 18,000 Indian nationals in the U.S. who were being viewed as illegal immigrants by the Trump administration.

"The United States is vigorously enforcing its border, tightening immigration laws, and removing illegal migrants. These actions send a clear message: illegal migration is not worth the risk," a U.S. Embassy spokesperson said here on Tuesday in response to a question on the deportation of the Indian nationals.

Turned away

The U.S. started military repatriation flights after Donald Trump took over as President

- Indian sources point out the latest repatriation is unique as it is being done using a military aircraft
- Trump had earlier said that Prime Minister Narendra Modi "will do what's right when it comes to taking back illegal Indian immigrants from America."
- Tuesday's exercise indicates a continued dialogue between the Trump administration and the Indian authorities

Major crackdown: A file photo of detained immigrants being boarded on a U.S. C-17 military aircraft last month. REUTERS

Indian sources, however, pointed out that while the deportation of Indian nationals who had landed in the U.S. through dubious means was not new, the use of a military aircraft to carry out the task was a new method.

The U.S. Department of Homeland Security had flown out a "large-frame charter removal flight" on October 22, 2024 carrying Indian nationals who had attempted to enter the U.S. illegally.

In a statement, the DHS had informed that since June 2024, the outfit had "removed or returned" over 1,60,000 individuals and operated around 495 international repatriation flights to "more than 145 countries - including India".

Tuesday's exercise indicates a continued dialogue between the Trump administration and the Indian authorities. External Affairs Minister S. Jaishankar had met the new U.S. Secretary of State, Marco Rubio, soon after the January 20 swearing-in of Mr. Trump.

'Duty bound'

Responding to a question from the media regarding the U.S. position, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal clarified last week that India would take back its citizens only after confirming their nationality.

"... Not just in the United States but anywhere in the world, if they are Indian nationals, and they are overstaying or they are in a particular country without proper documentation, we will take them back, provided documents are shared with us so that we can verify their nationality that they are indeed Indians," Mr. Jaiswal said.

Indian sources informed that New Delhi is "duty bound" to take back Indian citizens if they are found to be staying in foreign countries by using illegal means but also pointed out that there is an air of uncertainty within the U.S. over the tough immigration policy and because of defunding of several federally funded projects.

Since the inauguration of Mr. Trump on January 20, the issue of "illegal immigration" has been in the spotlight. It was a major poll plank during his campaign. It has been learnt that Mr. Modi is expected to reach the U.S. on February 12. He is among a number of foreign leaders like U.K. Prime Minister Keir Starmer and Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba who are scheduled to meet Mr. Trump in the next few days.

पृष्ठभूमि:

- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के प्रशासन के तहत सैन्य विमानों द्वारा अवैध भारतीय प्रवासियों को निर्वासित करने के साथ, अमेरिका ने अपने आव्रजन अभियान को तेज कर दिया है।
- अमेरिका में अनुमानित 7,25,000 अवैध भारतीय हैं, इस कदम से हजारों भारतीय नागरिक प्रभावित होंगे।
- भारत ने छात्रों और पेशेवरों के लिए कानूनी प्रवास मार्गों की रक्षा करने के उद्देश्य से, उनकी नागरिकता सत्यापित करने के बाद अवैध प्रवासियों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा में आव्रजन, द्विपक्षीय व्यापार और कूटनीतिक सहयोग पर उच्च स्तरीय चर्चा होगी।

ट्रम्प प्रशासन के तहत बड़े पैमाने पर निर्वासन:

- ट्रम्प प्रशासन अवैध प्रवासियों को लक्षित कर रहा है, जिसके कारण बड़े पैमाने पर निर्वासन हो रहा है।

- **मुख्य आँकड़े:**

- o 20,407 अवैध भारतीय ट्रम्प के आव्रजन रडार के अंतर्गत हैं।
- o 17,940 भारतीय अमेरिकी आव्रजन न्यायालयों द्वारा अंतिम निष्कासन आदेशों के अधीन हैं।
- o 2,467 भारतीय वर्तमान में ICE (आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन) के तहत हिरासत केंद्रों में हैं।

- **नवीनतम निर्वासन उड़ानें:**
  - o एक C-17 अमेरिकी सैन्य विमान ने टेक्सास के सैन एंटोनियो से 205 भारतीय नागरिकों को वापस भारत पहुँचाया।
  - o इनमें से ज़्यादातर लोग गुजरात और पंजाब से हैं।
  - o भारत ने निर्वासित व्यक्तियों को स्वीकार करने से पहले राष्ट्रीयता की पुष्टि करने पर ज़ोर दिया है।

ट्रम्प की आव्रजन कार्रवाई और नीति परिवर्तन:

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने अवैध आव्रजन को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है, सख्त उपाय लागू किए हैं:
- **बढ़ी हुई निर्वासन रणनीतियाँ:**
  - o वाणिज्यिक उड़ानों के बजाय सैन्य विमानों का उपयोग निर्वासन के लिए किया जा रहा है।
  - o ICE बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए FBI, DEA और बॉर्डर पैट्रोल के साथ समन्वय कर रहा है।
  - o जनवरी में निर्वासन गिरफ़्तारियों में तीन गुना वृद्धि हुई, एक ही सप्ताह में 1,000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया।
- **नए आव्रजन उपाय:**
  - o ICE ने बिडेन के प्रशासन के तहत दी गई कानूनी सुरक्षा को हटा दिया है।
  - o CBP One मोबाइल ऐप, जो प्रवासियों को सीमा प्रवेश अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने की अनुमति देता था, बंद कर दिया गया है।
  - o अवैध अप्रवासियों से पैदा हुए बच्चों के लिए जन्मसिद्ध नागरिकता समाप्त कर दी गई है।
- **हिरासत केंद्रों का विस्तार:**
- गुआंतानामो बे हिरासत केंद्र को 30,000 प्रवासियों को रखने के लिए फिर से तैयार किया जा रहा है।
- कोलोराडो में बकले स्पेस फोर्स बेस का इस्तेमाल भी प्रवासियों को हिरासत में रखने के लिए किया जा रहा है।

भारत की कूटनीतिक प्रतिक्रिया और चिंताएँ:

- भारत ने द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित किए बिना अप्रवासन मुद्दे को प्रबंधित करने के लिए कूटनीतिक प्रयास किए हैं:

निर्वासन पर भारत की स्थिति:

- भारत ने राष्ट्रीयता सत्यापन की पुष्टि होने पर अवैध अप्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की है।
- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो को भारत के रुख से अवगत कराया।
- भारत संगठित अपराध और मानव तस्करी से जुड़े होने के कारण अवैध अप्रवास के खिलाफ है।

प्रवास के लिए कानूनी रास्ते सुनिश्चित करना:

- 2024 में भारतीय नागरिकों को 1 मिलियन से अधिक वीजा जारी किए गए, जिनमें रिकॉर्ड संख्या में छात्र और व्यावसायिक वीजा शामिल हैं।
  - o पिछले वित्तीय वर्ष में जारी किए गए H-1B वीजा का 72% भारतीय पेशेवरों को दिया गया।
  - o ट्रम्प ने आश्वासन दिया है कि H-1B वीजा कार्यक्रम जारी रहेगा, हालांकि कुछ सुधार पेश किए जा सकते हैं।

- **भारत-अमेरिका वार्ता में चुनौतियाँ:**
  - o भारत ने राजनीतिक प्रतिक्रिया से बचने के लिए विवेकपूर्ण निर्वासन उपायों की माँग की है।
  - o भारतीय प्रवास कार्यक्रमों पर संभावित प्रतिबंधों को लेकर चिंताएँ बनी हुई हैं।

आव्रजन नीति पर ट्रम्प का आर्थिक लाभ:

- राष्ट्रपति ट्रम्प ने आव्रजन अनुपालन को लागू करने के लिए व्यापार नीतियों का लाभ उठाया है:
- गैर-सहकारी देशों पर टैरिफ लगाना
-
  - o कोलंबिया ने निर्वासन उड़ान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया - ट्रम्प ने कोलंबियाई वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की।
  - o कनाडा और मैक्सिको को भी टैरिफ की धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे उन्हें सीमा प्रवर्तन को बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा।
  - o अमेरिकी कांग्रेस निर्वासन आदेशों के साथ सहयोग नहीं करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है।
- **इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है**
  - o जबकि भारत ने अमेरिका के साथ सहयोग किया है, वह भविष्य के व्यापार प्रतिबंधों के प्रति सतर्क है।
  - o भारत का ध्यान अपने कुशल कार्यबल प्रवास की रक्षा करने और आर्थिक प्रतिशोध से बचने पर है।

अमेरिका में भारतीय समुदाय पर प्रभाव:

- **अनिर्दिष्ट प्रवासियों में भय और अनिश्चितता**
  - o कई भारतीय अनिर्दिष्ट श्रमिक बढ़ती गिरफ़्तारियों के कारण सार्वजनिक स्थानों से बच रहे हैं।
  - o कार्यस्थलों और घरों में हिरासत में लिए जाने से कम वेतन वाले नौकरी क्षेत्रों में आर्थिक तनाव पैदा हो गया है।
- **कानूनी प्रवासी भी प्रभावित**
  - o H-1B वीज़ा कार्यक्रम अनिश्चित बना हुआ है, जिसमें प्रायोजन आवश्यकताओं में संभावित बदलाव शामिल हैं।
  - o कई भारतीय छात्रों को सख्त वीज़ा नवीनीकरण नीतियों का डर है।
- **भारत कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है**
  - o भारत स्थिति पर बारीकी से नज़र रख रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि कानूनी प्रवासियों के अधिकारों की रक्षा की जाए।
  - o अमेरिकी नीति निर्माताओं के साथ राजनयिक जुड़ाव रोज़गार-आधारित आव्रजन कार्यक्रमों को संरक्षित करने पर केंद्रित है।

Page 01 : GS 2 : International Relations

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लगाने को लागू होने से कुछ घंटे पहले ही स्थगित कर दिया, जिससे उत्तरी अमेरिकी व्यापार युद्ध एक महीने के लिए टल गया।

China hits back at U.S. with goods tariffs, probe into Google

Agence France-Presse
BEIJING

China said on Tuesday it would impose tariffs on imports of U.S. energy, vehicles and equipment, firing a return salvo in an escalating trade war between the world's two biggest economies.

U.S. President Donald Trump on Saturday had announced sweeping measures against major trade partners Canada and Mexico, while goods from China were hit with an additional 10% tariff on top of the duties they already endure.

Minutes after they came into effect, Beijing unveiled levies of 15% on imports of coal and liquefied natural gas from the U.S., while crude oil, agricultural machinery, big-engined vehicles, and pick-up trucks face 10% duties.

China is a major market for U.S. energy exports and according to Beijing customs data, imports of oil, coal and LNG totalled more than $7 billion last year.

But that is dwarfed by China's imports from more friendly powers such as Russia, from which it purchased $94 billion-worth last year.

'Unilateral hike'

Beijing said the measures were in response to the "unilateral tariff hike" by Washington.

The U.S. decision, China said, "seriously violates World Trade Organization rules, does nothing to resolve its own problems, and disrupts normal economic and trade cooperation between China and the United States". Beijing said it would file a complaint with the WTO over the "malicious" levies.

"I think the retaliation is not aggressive, as China only targets some U.S. products, in response to the U.S. tariff on all China's exports to the U.S.," Zhang Zhiwei of Pinpoint Asset Management said in a note. "This is likely only the beginning of a long process for the two countries to negotiate".

Shoppers walk by a Calvin Klein store in Beijing. The brand is owned by PVH Group into which China announced a probe on Tuesday. AP

Probes launched

Alongside its tariffs, China announced a probe into U.S. tech giant Google and the addition of U.S. fashion group PVH Corp.– which owns Tommy Hilfiger and Calvin Klein – and biotech giant Illumina to a list of "unreliable entities".

Beijing's State Administration for Market Regulation said the U,S, tech giant was "suspected of violating the Anti-Monopoly Law of the People's Republic of China".

It has "launched an investigation into Google in accordance with the law" as a result, the administration said in a statement.

It did not provide further details about the allegations against Google.

The U.S. tech behemoth's core search engine and many of its services are blocked in mainland China, where U.S. Internet titans have long struggled with doing business.

Google in 2011 abandoned its Chinese-language search engine in the mainland and transferred it to Hong Kong.

The probe into PVH and Illumina would "safeguard national sovereignty, security and development interests, in accordance with relevant laws", China's Commerce Ministry said in a statement.

"The above two entities violate normal market transaction principles, interrupt normal transactions with Chinese enterprises, and take discriminatory measures against Chinese enterprises," it added.

China in September said it was investigating PVH for an "unreasonable" boycott of cotton from its Xinjiang region, where Beijing is accused of widespread rights violations.

Beijing also unveiled fresh export controls on rare metals and chemicalsincluding tungsten, tellurium, bismuth, and molybdenum, used in a range of industrial appliances.

Mr. Trump has said his tariffs aimed to punish countries for failing to halt flows of illegal migrants and drugs into the U.S. He said on Monday that he planned a call with Chinese counterpart Xi Jinping in the next 24 hours.

RELIEF FOR CANADA, MEXICO
» PAGE 14

Sensex rebounds as Canada, Mexico get tariff breather

MUMBAI

The Indian stock market bounced back sharply on Tuesday with its biggest uptick in a month, fuelled by the U.S.'s decision to pause the blanket tariffs on imports from Canada and Mexico that had spooked global markets and currencies on Monday. » PAGE 12

- हालांकि, चीन के साथ तनाव बढ़ गया क्योंकि बीजिंग ने एंटीट्रस्ट उल्लंघन के लिए Google की जांच करके और अमेरिकी कोयला, LNG, तेल और कृषि उपकरणों पर नए टैरिफ लगाकर अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की।
- ट्रंप ने व्यापार असंतुलन का हवाला देते हुए यूरोपीय संघ पर आगामी टैरिफ का भी संकेत दिया। व्यवसाय संभावित व्यवधानों के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि भारत सहित एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार के रूप में यूरोपीय संघ की भूमिका एक व्यापक वैश्विक व्यापार संघर्ष के बारे में चिंताएं पैदा करती है।

अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन के साथ ट्रम्प का व्यापार युद्ध

- अपने पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने चीन के साथ व्यापार युद्ध शुरू किया, जिसके परिणामस्वरूप प्रतिशोधात्मक टैरिफ और प्रतिवाद हुए।
- इसके परिणामस्वरूप अंततः 15 जनवरी, 2020 को चरण एक सौदा हुआ, जिसका उद्देश्य संरचनात्मक सुधार और चीन द्वारा खरीद में वृद्धि करना था।

- हालांकि, बाद के विश्लेषणों से पता चला कि चीन ने न तो अपनी खरीद प्रतिबद्धताओं को पूरा किया और न ही संरचनात्मक सुधारों को लागू किया।

चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ और भारत को संभावित लाभ

- चीनी वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ ने भारत सहित अन्य देशों के लिए अमेरिका को अपने निर्यात बढ़ाने के अवसर पैदा किए।
- ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के एक अध्ययन में पाया गया कि ट्रम्प के टैरिफ उपायों के बाद, 2017 और 2023 के बीच व्यापार विचलन का चौथा सबसे बड़ा लाभार्थी भारत था।
- इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उल्लेखनीय लाभ हुआ, 2017 से यू.एस. आयात में भारत की हिस्सेदारी दस गुना बढ़ गई, जो मुख्य रूप से आईफ़ोन जैसे दूरसंचार उपकरणों द्वारा संचालित है।
- चीनी वस्तुओं पर वर्तमान 10% टैरिफ के साथ, भारतीय निर्यातकों को यू.एस. में अपने बाजार हिस्से का विस्तार करने की और संभावना दिख रही है।
- भारतीय निर्यातकों को चीन पर टैरिफ बढ़ने की आशंकाओं के कारण अधिक ऑर्डर मिल रहे हैं, जैसा कि पिछले व्यापार युद्ध के दौरान हुआ था।

भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता की चुनौतियाँ

- लाभ के बावजूद, भारत उच्च तकनीक निर्माण में अन्य एशियाई देशों से पीछे है।
- कोरिया और ताइवान सेमीकंडक्टर पर हावी हैं, जबकि चीन अभी भी यू.एस. इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 27% आपूर्ति करता है।

व्यापार को आकर्षित करने की भारत की रणनीति

- व्यापार बदलावों से लाभ उठाने के लिए, भारत ने टैरिफ को सुव्यवस्थित करने के लिए केंद्रीय बजट में प्रमुख आयातों पर सीमा शुल्क में कटौती की।
- यह कदम भारत की टैरिफ संरचना को सरल बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

ट्रम्प के टैरिफ का प्रभाव

- कनाडा, मैक्सिको और चीन पर ट्रम्प के टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं की लागत बढ़ेगी, जिसका अनुमानित वार्षिक बोझ प्रति परिवार $1,200 से अधिक होगा।
- टैरिफ आयात का सामना कर रहे अमेरिकी उत्पादकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी कीमतें बढ़ाएँ, जिससे मुद्रास्फीति और बढ़ेगी।

अमेरिकी मुद्रास्फीति और भारतीय निर्यात पर इसका प्रभाव

- अमेरिका और यूरोप में उच्च मुद्रास्फीति ने पहले ही भारतीय निर्यात को प्रभावित किया है, विशेष रूप से रत्न, आभूषण और वस्त्र जैसे श्रम-गहन क्षेत्रों में।
- बढ़ती लागत और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान भारतीय वस्तुओं की मांग को और कमजोर कर सकते हैं।

कर नीति और आर्थिक बोझ

- उच्च टैरिफ, संभावित मंदी के प्रभावों के साथ, अधिकांश अमेरिकी परिवारों के लिए शुद्ध कर वृद्धि का कारण बन सकते हैं।

अमेरिकी निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता पर

- अर्थशास्त्रियों ने समझाया कि मैक्सिकन और कनाडाई आयातों पर ट्रम्प के 25% टैरिफ ने अमेरिकी निर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता को कमजोर कर दिया है, जिससे यूरोप और एशिया में प्रतिद्वंद्वियों को लाभ मिला है।

अमेरिकी ऑटो उद्योग पर प्रभाव

- अमेरिकी कारें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के पुर्जों पर निर्भर हैं, जिससे इन देशों पर टैरिफ से उत्पादन लागत बढ़ जाती है।
- परिणामस्वरूप, अमेरिका में निर्मित कारें अधिक महंगी हो जाती हैं, जिससे खरीदार जापान, जर्मनी और कोरिया से आयात करना पसंद करते हैं, जो टैरिफ के अधीन नहीं हैं।

आगे बढ़ने का जोखिम

- विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि यदि अमेरिकी उपभोक्ता सस्ती विदेशी कारों की ओर रुख करते हैं, तो ट्रम्प इसे अनुचित प्रतिस्पर्धा के रूप में देख सकते हैं और इनमें से किसी एक तरीके से प्रतिक्रिया कर सकते हैं:

सभी आयातित कारों पर 25% टैरिफ लगाना

- जापान, जर्मनी और कोरिया के साथ निर्यात प्रतिबंधों पर बातचीत करना
- यह प्रतिशोधात्मक चक्र वैश्विक व्यापार युद्ध को और बढ़ा सकता है, जिससे कई उद्योग और अर्थव्यवस्थाएँ प्रभावित हो सकती हैं।

GEO IAS
It's about quality

भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध गहरे ऐतिहासिक और सामरिक महत्व के हैं।

India-Indonesia ties as a beacon for global relations

Anindya Bakrie

is Chair of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN), and the CEO of Bakrie & Brothers

It was a great honour for this writer to have accompanied President Prabowo Subianto of Indonesia, who was the chief guest at India's spectacular 76th Republic Day celebrations. The magnificence of the occasion was not only reflected in the vibrant displays of India's democracy, diversity and military strength, but was also a timely reminder of the deep and enduring relationship between the countries, which can be a beacon for wider international relations.

The evolution of ties

Indeed, as India celebrated its first Republic Day in 1950, marking its new destiny as a sovereign and democratic nation, it was Indonesia's founding father, President Sukarno, who graced the occasion as chief guest.

In subsequent decades, as the two countries embraced their independence, they have built strong ties, spanning economics, politics and culture. In fact, this year was the fourth time that an Indonesian President has been chief guest at the Republic Day celebrations. Mr. Prabowo's visit, and his meeting with Indian Prime Minister Narendra Modi, highlighted the shared ambition of the two leaders to further increase collaboration in areas that include trade, maritime security, health and technology.

As two of the world's largest and fastest growing economies, Indonesia and India have immense potential to become the cornerstone for prosperity and security for the entire Indo-Pacific region and beyond. In particular, this writer's visit convinced him that there are three key areas of trade, security and geo-politics.

First, whilst the two countries signed a trade agreement back in 1966, from today's vantage point there is a huge amount that can be done to grow economic ties between the two countries. As Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce, this writer co-chaired the CEOs Forum alongside Indian business leader Ajay S. Shriram in New Delhi. Bringing together senior business leaders from India and Indonesia, we identified five key sectors that should be prioritised to unlock mutual growth, boost innovation and strengthen bilateral ties, i.e., in energy, food and agriculture, health care, manufacturing and technology.

In strengthening their bonds, the two countries can lay the foundation for a more prosperous and sustainable future for Asia and the world

Trade and security as pillars

Throughout the discussions, it became clear that there are immense opportunities to increase bilateral trade, which currently stands at just under $30 billion. There is the potential to quadruple the volume of trade in the next 10 years. Ambitious growth targets reflect the confidence the two nations have in each other's potential and in their continued partnership.

Against a backdrop of global economic uncertainty, India and Indonesia are forecast to grow by 6.5% and 5.1%, respectively, this year, which is well above the global growth average of 3.3%. This reflects their expanding markets, young and dynamic workforces as well as growing consumer demand.

There is also huge untapped potential for both countries to benefit from intelligent investment that can position them as leaders in energy transition. While Indonesian investment in India stands at $653.8 million and India has invested $1.56 billion in Indonesia, this only scratches the surface of what is possible. By deepening their investments and supply chains in sectors such as clean energy, technology and manufacturing, the two countries can lead the global effort against climate change.

Security is the second pillar of the India-Indonesia partnership. In recent years, they have made significant strides in strengthening defensive ties, culminating in the Comprehensive Strategic Partnership in 2018, which is already yielding significant dividends, particularly in enhancing maritime security in their shared waters.

But defensive cooperation is only one aspect of their multifaceted relationship. During Mr. Prabowo's visit, Mr. Modi and Mr. Prabowo committed to strengthening collaboration in areas such as counterterrorism and cyber security to keep the two countries safe.

As two large, populous nations with growing military capabilities, this is essential if the two countries are to address the complex geopolitical dynamics of the Indo-Pacific and safeguard its stability and prosperity for generations to come.

International relations

A third element of the bilateral relationship is how it fits in the global context. Outside of the Indo-Pacific, India and Indonesia are both navigating a geo-political environment that is constantly shifting. At the start of the year, Indonesia was formally invited to join the BRICS group of emerging economies. In that club of powerful emerging economies, it joins India and, of course, China too. At the same time, both Indonesia and India have important relationships with the United States and other western countries. The new U.S. administration led by President Donald Trump has threatened to introduce a new set of tariffs, and it remains to be seen what will happen.

It is obvious that tariffs and non-tariff barriers are impediments to free trade and carry risks for the global economy. Indonesia, as a key source of natural resources such as nickel, copper, tin and bauxite, wants to be able to export to the U.S., India and other markets.

President Prabowo's visit to India was a reminder of the importance of Indonesia's bilateral relationship with Indonesia. Their partnership, 76 years old, continues to grow in strength and their potential to shape the future of the Indo-Pacific and the global economy is vast. As the two countries continue to work together through trade, security and their geo-political ties, they will not just strengthen the bonds between the two great nations but also lay the foundation for a more prosperous and sustainable future for Asia and the world.

It's about quality

- भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की हालिया यात्रा ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को उजागर किया।
- यह यात्रा उनके साझा इतिहास, आर्थिक क्षमता और सुरक्षा सहयोग की याद दिलाती है, जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र और वैश्विक भू-राजनीतिक गतिशीलता को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को पुष्ट करती है।

भारत-इंडोनेशिया संबंध: ऐतिहासिक आधार और संबंधों का विकास

स्वतंत्रता के लिए साझा संघर्ष

- भारत और इंडोनेशिया के बीच ऐतिहासिक संबंध उपनिवेशीकरण, स्वतंत्रता और उसके बाद आत्मनिर्णय की खोज के साझा अनुभवों में गहराई से निहित हैं।
- दोनों देशों के बीच संबंध 20वीं सदी में उनके स्वतंत्रता आंदोलनों की अवधि से शुरू हुए हैं, जब दोनों देश एक-दूसरे के कुछ वर्षों के भीतर स्वतंत्र गणराज्य के रूप में उभरे थे।
- भारत ने 1947 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में अपनी राह बनाई।
- इंडोनेशिया ने 1945 में डच औपनिवेशिक शासन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की, हालांकि 1949 तक इंडोनेशिया की संप्रभुता को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं मिली थी।

- **प्रतीकात्मक शुरुआत: 1950 का गणतंत्र दिवस निमंत्रण**
  - o इस पारस्परिक सम्मान का पहला औपचारिक संकेत 1950 में भारत के उद्घाटन गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हुआ।
  - o इंडोनेशिया के संस्थापक पिता और पहले राष्ट्रपति सुकर्णो को मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, यह सम्मान आपसी समझ और सहयोग पर आधारित एक राजनयिक संबंध की शुरुआत का प्रतीक था।
  - o इस क्षण ने लोकतंत्र, गुटनिरपेक्षता और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के साझा मूल्यों की विशेषता वाले रिश्ते की शुरुआत की।

- **राजनयिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना**
  - o जब दोनों राष्ट्र नए संप्रभु राज्यों के रूप में अपनी यात्रा पर निकले, तो उनके नेताओं ने मजबूत राजनयिक और आर्थिक संबंध विकसित करने के महत्व को पहचाना।
  - o उनके संबंधों के शुरुआती वर्षों में अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में सहयोग की विशेषता रही, खास तौर पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) के माध्यम से, जिसे आकार देने में भारत और इंडोनेशिया दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
  - o 20वीं सदी के मध्य में स्थापित NAM ने पश्चिमी और पूर्वी ब्लॉकों के शीत युद्ध विभाजन के लिए एक वैकल्पिक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, जिसमें तीसरे रास्ते पर जोर दिया गया जो शांति, सहयोग और महाशक्तियों के प्रभाव से स्वतंत्रता को बढ़ावा देता था।

- **द्विपक्षीय जुड़ाव और सांस्कृतिक आदान-प्रदान**
  - o अपनी स्वतंत्रता के बाद के दशकों में, दोनों देशों ने विभिन्न द्विपक्षीय जुड़ावों के माध्यम से अपने संबंधों को मजबूत किया।
  - o भारत और इंडोनेशिया ने व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौतों सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए और सांस्कृतिक आदान-प्रदान विकसित किए, जिससे उनके संबंध और गहरे हुए।
  - o ये आदान-प्रदान दोनों देशों की समृद्ध सांस्कृतिक विरासतों को दर्शाते हैं, जिसने आपसी सम्मान और सहयोग के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया।

- **लगातार नेतृत्व यात्राएँ**
  - o इंडोनेशियाई राष्ट्रपतियों की बार-बार भारत यात्राएँ, जिनमें राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की हाल की यात्रा भी शामिल है, इस साझेदारी की स्थायी प्रकृति को रेखांकित करती हैं।
  - o राष्ट्रपति प्रबोवो की यात्रा चौथी बार हुई जब किसी इंडोनेशियाई नेता को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, जो संबंधों के निरंतर और बढ़ते महत्व का प्रमाण है।

o ये यात्राएँ द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने और व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और शिक्षा सहित विविध क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते खोलने में सहायक रही हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों के प्रमुख पहलू

- **विकास के स्तंभ के रूप में व्यापार**
  o आर्थिक सहयोग भारत-इंडोनेशिया संबंधों का एक प्रमुख पहलू रहा है।
  o हालाँकि 1966 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन आर्थिक संबंधों के विस्तार की अपार संभावनाएँ अभी भी मौजूद हैं।
  o वर्तमान में, द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 बिलियन डॉलर है, लेकिन अगले दशक में इस आँकड़ों को चौगुना करने की महत्वाकांक्षा है।
  o हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित सीईओ फोरम में, जिसकी सह-अध्यक्षता इंडोनेशियाई चैंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष और भारतीय व्यापार नेता अजय एस. श्रीराम ने की, विकास के लिए पाँच प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई: ऊर्जा, खाद्य और कृषि, स्वास्थ्य सेवा, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी।
  o नवाचार पर ध्यान केंद्रित करके और द्विपक्षीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके, दोनों देश नए आर्थिक अवसरों को खोल सकते हैं।
  o भारत के लिए 6.5% और इंडोनेशिया के लिए 5.1% की अनुमानित आर्थिक वृद्धि दर के साथ, दोनों देश वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद फलने-फूलने की अच्छी स्थिति में हैं।
- **सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग**
  o सुरक्षा सहयोग भारत-इंडोनेशिया साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है।
  o 2018 की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने रक्षा संबंधों को काफी मजबूत किया है, खासकर समुद्री सुरक्षा में।
  o व्यापक तटरेखा और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन वाले दो देशों के लिए अपने जल की सुरक्षा सुनिश्चित करना सर्वोपरि है।
  o राष्ट्रपति प्रबोवो की यात्रा ने आतंकवाद विरोधी और साइबर सुरक्षा सहयोग के लिए प्रतिबद्धताओं को और मजबूत किया।
  o हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विकसित हो रहे भू-राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की रक्षा के लिए निकट सैन्य और रणनीतिक सहयोग आवश्यक है।
  o दोनों देश साइबर खतरों और क्षेत्रीय विवादों सहित आम सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने की आवश्यकता को पहचानते हैं।

भारत-इंडोनेशिया संबंधों का भू-राजनीतिक महत्व

- अपने द्विपक्षीय संबंधों से परे, भारत और इंडोनेशिया वैश्विक भू-राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- इंडोनेशिया को हाल ही में ब्रिक्स समूह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है, जो इसे भारत और चीन सहित अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ जोड़ता है।
- इस बीच, दोनों राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी शक्तियों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं।
- हालांकि, वैश्विक व्यापार चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसमें संभावित अमेरिकी टैरिफ शामिल हैं जो दोनों अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं।
- एक संसाधन संपन्न राष्ट्र के रूप में, इंडोनेशिया अमेरिका और भारत जैसे बाजारों में निकल, तांबा, टिन और बॉक्साइट जैसी प्रमुख वस्तुओं का निर्यात करना चाहता है।

- इस बीच, भारत का विस्तारित विनिर्माण क्षेत्र पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार व्यवस्था के अवसर प्रस्तुत करता है।

निष्कर्ष

- राष्ट्रपति प्रबोवो की यात्रा ने भारत और इंडोनेशिया के बीच गहरी और स्थायी साझेदारी की पुष्टि की।
- उनका रिश्ता, जो अब 76 साल पुराना है, व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग से प्रेरित होकर विकसित हो रहा है।
- जैसे-जैसे वे वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक बदलावों को नेविगेट करते हैं, उनका सहयोग इंडो-पैसिफिक और उससे आगे के भविष्य को आकार देने में सहायक होगा।
- संबंधों को मजबूत करके, भारत और इंडोनेशिया न केवल अपनी समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ाते हैं बल्कि एक अधिक स्थिर और टिकाऊ दुनिया में भी योगदान देते हैं।

GEO IAS
It's about quality

केंद्रीय बजट में करों में बड़ी कटौती की गई है, जिसका लाभ ₹7 लाख से अधिक आय वाले करदाताओं को मिलेगा। देनदारियों को कम करने के लिए छूट और रियायतें बढ़ाई गई हैं, हालांकि इससे अनुमानित ₹1 लाख करोड़ राजस्व का नुकसान हो सकता है।

Why the tax cuts are a one way gamble

In a world where expenditure by the government is directly linked to tax revenue, any shortfall on the tax side will show up on the expenditure side as well. Despite the fall of 8% in the effective tax rate, the Budget has estimated direct tax collection to go up by 14%

ECONOMIC NOTES

Rohit Azad
Indranil Chowdhury

It would not be an exaggeration to say that this is the biggest tax cut that the middle class has ever got in any Union Budget. To be sure, the tax-paying middle class in India is nowhere near "middle" of the income spectrum and, hence, those who would directly benefit from these cuts are a minuscule minority (between 2-3% of the population). Nevertheless, it is indeed a significant cut in tax rates for every class of taxpayer. For those earning between ₹7-₹12 lakh a year, it is a complete tax rebate, which was earlier applicable to only those below ₹7 lakh. For others earning more than ₹12 lakh, the exemption limit has increased from ₹3 to ₹4 lakh. The rest of the tax slabs have also changed favourably along with a cut in the marginal tax rates. So, everyone earning more than ₹7 lakh stands to gain in taxes payable. No wonder this step, as noted by the Finance Minister, will lead to a fall in tax revenue to the tune of ₹1 lakh crore. This is 8% of the direct income tax collection of ₹12.57 lakh crore in the current year.

Budgets are an exercise in both a redistribution of income (through differential variation in tax rates) and affecting the level of economic activity through its expenditure decisions.

Since the tax rebate has implications for both, and a lot of the plans of the 2025 Budget ride on it, this piece primarily focuses on this unprecedented fall in income tax rates.

The logic behind the tax rebates

Despite the fall of 8% in the effective tax rate as a result of this policy, the Budget has estimated direct tax collection to go up by 14%. A simple arithmetic calculation would tell us that this requires the rise of income to be around 24% (see Box 1). With a projected growth of 10.1% in nominal GDP, this means more than double the growth in taxpayers' income. This may or may not happen. Let's discuss each of the two scenarios.

First, the optimistic scenario. In the backdrop of higher tax exemption limits (from ₹7 to ₹12 lakh for zero tax and ₹3 to ₹4 lakh for those earning more than 12 lakh), this would require either a significant rise in the number of people earning more than ₹12 lakh and/or a significant rise in the income of the current taxpayers, that is, what economists would call higher tax buoyancy. If it's the latter, this means further concentration of income in the hands of the upper classes. This may just further the K-shaped growth that the country has witnessed since the pandemic. And if it's the former, this may reflect some upward mobility at the upper end of the income spectrum.

Worst-case scenario

Now, the pessimistic scenario. If the tax buoyancy does not quite work out, the implication of it is going to fall on the poor and disadvantaged of this country.

In a world where expenditure by the government is directly linked to tax revenue, any shortfall on the tax side will show up on the expenditure side as well. With the Fiscal Responsibility Budgetary Management Act (FRBM) in place, governments are bound by how much they can spend over and above their tax revenue and that deficit limit is set in the Budget every year (see Box 2). The state effectively loses control over how much it can spend, and the fiscal policy becomes pro-cyclical (it increases or decreases with GDP) instead of countercyclical as it is supposed to be. The idea of fiscal policy arose in economics from the assumption that it could be expanded in conditions of slowdown and contracted during booms. Adherence to FRBM does the exact opposite.

This government's track record on strictly adhering to its deficit targets is quite telling. In a year, when the government was worried about a four-year low in economic growth, it has dared to revise its deficit target down from 5% as announced in the 2024 Budget to 4.8%. No wonder this fall in deficit has been managed through an almost across the board cut in expenditures compared to the figures announced in Budget 2024 (Chart 1 shows categories of expenses where there has been a fall). The left column in the chart shows the difference between what the Finance Minister announced last year and what the revised expenses actually were. As is evident, there has been a fall of ₹1 lakh crore in total expenditure. So, the government fell way short of its 2024 promises in terms of its commitments. The promises made in Budget 2025 (the right column of chart 1) are a significant jump from the revised figures of the last Budget. These promises can only be fulfilled if revenue plans turn out to be correct otherwise there would have to be similar (or more) cuts in the actual expenses made in 2025-26.

That the government is extremely serious about managing its deficit becomes clearer if one looks at some of the schemes that have been associated with the Prime Minister. Chart 2 presents the difference between the Budget and Revised Estimates for some of these important schemes. It can be seen that the cut has been across most of the flagship schemes. So, when this government promises fiscal consolidation, it really means it, no matter what the underlying economic circumstances are. The only exception to this rule is perhaps the pandemic where fiscal consolidation was paused for a brief while.

Fiscal consolidation or contraction?

What is additionally worrying on this count is that the Finance Minister has announced an even lower deficit target this Budget, down from 4.8% (RE 2024) to 4.4% (BE 2025). It's not fiscal consolidation alone, it's fiscal contraction. If a 4.8% couldn't deliver a turnaround in growth, a 4.4% is less likely to. Even if you were a fiscal hawk, now is not the time to be one. With growth slowing down, the economy requires exogenous stimuli (exogenous to the current level of activity), which propels the economy. Such an exogenous stimulus usually comes from exports, corporate investment or government expenditure. With the last lever gone (as expenditure becomes pro-cyclical), the government is effectively banking on exports and corporate investment to bring about a turnaround in growth. If we go by the 2025 Economic Survey, policymakers are not very optimistic about global demand, so it is clear they are expecting the corporate sector to take up the slack.

If corporate investment has not picked up despite tax cuts or aggressive capex spending over the last four years, there has to be the expectation that the income tax cuts would increase consumption demand, which would require an increase in investment, thereby setting a virtuous cycle of growth begetting growth. Yet again, we are back to income tax cuts. Does putting all your eggs in one basket make sense when things are not going your way? And yet, this is what the government seems to have done. It's a one way gamble.

Rohit Azad teaches economics at Jawaharlal Nehru University, New Delhi. Indranil Chowdhury teaches economics at PGDAV college, DU

Cut in taxes, rise in income?

The Union Budget for 2025-26 gave a significant cut in tax rates for every class of taxpayer. For those earning between ₹7-₹12 lakh a year, it is a complete tax rebate, which was earlier applicable to only those below ₹7 lakh. For others earning more than ₹12 lakh, the exemption limit has increased from ₹3 to ₹4 lakh

Box 1

$$T = t \cdot Y$$

$$\frac{\Delta T}{T} = \frac{\Delta t}{t} + \frac{\Delta Y}{Y} + \left(\frac{\Delta t}{t} * \frac{\Delta Y}{Y}\right)$$

$$\therefore \frac{\Delta T/T}{0.14} = \frac{-0.08}{-0.08} + \frac{1+\Delta t/t}{0.92} \frac{\Delta Y}{Y}$$

$$100 * \frac{\Delta Y}{Y} = 23.9\,\%$$

where,

T = income tax revenue
t = average income tax rate
Y = total taxpayers' income

Box 2

$$G - T = d \cdot Y$$
$$G = T + d \cdot Y$$
$$G = (t + d) \cdot Y$$

where,

G = total government expenditure
T = total tax revenue
Y = Output (GDP)
d = FRBM deficit target
t = total tax-GDP ratio

PTI

Chart 1: Delivery versus promises in fiscal expenditure

(in ₹ crore)

	RE 2024 minus BE 2024	BE 2025 minus RE 2024
Total expenditure	-1,04,025	3,48,858
Capital expenditure	-92,682	1,02,661
Rural development	-75,133	76,142
Urban development	-18,907	33,107
Education	-11,584	14,596
Agriculture	-10,992	30,578
Food subsidy	-7,830	6,000
Health	-1,255	10,279

RE: Revised Estimate; BE: Budget Estimate

Chart 2: Cut in expenditure of some flagship schemes

Difference between Revised Estimate and Budget Estimate of 2024-25 (in ₹ crore)

Jal Jeevan Mission	-47,469
PM Awas (Grameen)	-22,074
PM Awas (Urban)	-16,501
PM Garib Kalyan	-8,250
Swacch Bharat Mission	-2,841
PM-Poshan	-2,467
Rashtriya Krishi Vikas	-1,553
PM Anusuchit Jati Abhudaya	-1,340
PM Vanbadhu Kalyan	-670

Source: Authors' calculations, various budget documents, Government of India

THE GIST

- Budgets are an exercise in both a redistribution of income (through differential variation in tax rates) and affecting the level of economic activity through its expenditure decisions.
- This government's track record on strictly adhering to its deficit targets is quite telling. In a year, when the government was worried about a four-year low in economic growth, it has dared to revise its deficit target down from 5% as announced in the 2024 Budget to 4.8%.
- What is additionally worrying on this count is that the Finance Minister has announced an even lower deficit target this Budget, down from 4.8% (RE 2024) to 4.4% (BE 2025). It's not fiscal consolidation alone, it's fiscal contraction.

कर छूट के पीछे क्या तर्क है?

- घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना: ₹7-12 लाख/वर्ष कमाने वाले करदाता अब पूर्ण छूट के लिए पात्र हैं (पहले यह सीमा ₹7 लाख से कम आय वालों तक सीमित थी), जिससे उन्हें सालाना ₹70,000-₹1.1 लाख की बचत होगी।
- o ₹12 लाख से अधिक कमाने वालों के लिए यह छूट सीमा ₹3 लाख से बढ़ाकर ₹4 लाख कर दी गई, जिससे सभी आय समूहों पर कर का बोझ कम हो गया। इससे उपभोग, बचत और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए डिस्पोजेबल आय में वृद्धि होगी।
  o कमज़ोर निजी निवेश और अनिश्चित वैश्विक मांग के साथ, कर छूट का उद्देश्य घरेलू उपभोग को प्रोत्साहित करना है।

- राजस्व वृद्धि के लिए कर उछाल का लाभ उठाना: 8% कर दर में कमी के बावजूद, सरकार प्रत्यक्ष कर राजस्व (₹14.3 लाख करोड़) में 14% की वृद्धि की उम्मीद करती है, जिसके लिए करदाताओं के बीच 24% आय वृद्धि की आवश्यकता है। इसने कर स्लैब को सरल बनाया और अनुपालन में सुधार करने तथा करदाता आधार को व्यापक बनाने के लिए पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया।
- मध्यम वर्ग के कल्याण पर ध्यान: इन कर छूटों का व्यापक लक्ष्य मध्यम वर्ग का समर्थन करना है, जो मतदाताओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके कर बोझ को कम करके, सरकार उनकी वित्तीय भलाई को बढ़ाने तथा अधिक न्यायसंगत आर्थिक वातावरण को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

यदि कर उछाल काम नहीं करता है तो इसके क्या परिणाम होंगे?

- राजस्व में कमी: कर उछाल में विफलता से कर राजस्व अपेक्षा से कम होगा, जिसके परिणामस्वरूप बजट घाटा होगा। यह सरकार को आवश्यक सेवाओं तथा सामाजिक कार्यक्रमों में कटौती करने के लिए बाध्य कर सकता है, जिससे कमजोर आबादी के कल्याण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।
- चक्रीय-समर्थक राजकोषीय नीति: अपर्याप्त कर राजस्व सरकार को चक्रीय-समर्थक राजकोषीय नीति अपनाने के लिए बाध्य कर सकता है, जिससे आर्थिक मंदी के दौरान विकास को प्रोत्साहित करने के बजाय सार्वजनिक व्यय में कमी आ सकती है। यह आर्थिक मंदी को बढ़ा सकता है तथा सुधार प्रयासों में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- अनुपालन करने वाले करदाताओं पर कर का बोझ बढ़ाना: राजस्व में कमी की भरपाई के लिए, सरकार उन लोगों पर कर बढ़ा सकती है जो करों का भुगतान करना जारी रखते हैं, जिससे अनुपालन करने वाले करदाताओं पर बोझ बढ़ जाएगा और संभावित रूप से आगे अनुपालन और आर्थिक गतिविधि को हतोत्साहित किया जा सकेगा।

क्या यह 'राजकोषीय समेकन' है या 'राजकोषीय संकुचन'?

- वर्तमान दृष्टिकोण राजकोषीय समेकन के बजाय राजकोषीय संकुचन की ओर अधिक झुका हुआ प्रतीत होता है। वित्त मंत्री ने 2025-26 के लिए 4.4% का कम घाटा लक्ष्य निर्धारित किया है, जो पिछले वर्ष के 4.8% से कम है। यह वृद्धि को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विस्तार के बजाय राजकोषीय नीति को सख्त करने का सुझाव देता है।
- आलोचकों का तर्क है कि मौजूदा आर्थिक मंदी को देखते हुए इस तरह के संकुचनकारी उपाय गलत समय पर हैं, क्योंकि वे विकास को बढ़ावा देने वाली पहलों में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीमित करते हैं। उम्मीद है कि रिकवरी को बढ़ावा देने के लिए कॉर्पोरेट निवेश और निर्यात वृद्धि पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो कि कम सरकारी खर्च के कारण घरेलू मांग कमजोर रहने पर पर्याप्त नहीं हो सकता है।

पहलू	समेकन तर्क	संकुचन की आलोचना
घाटे का लक्ष्य	जीडीपी के 4.4% तक घटाया गया (वित्त वर्ष 24 में 4.8% से), वित्त वर्ष 29 तक 3% का लक्ष्य	धीमी वृद्धि (अनुमानित 10.1% नाममात्र जीडीपी) के दौरान घाटे में आक्रामक कटौती से रिकवरी में बाधा उत्पन्न होने का जोखिम है
राजस्व रणनीति	अनुपालन लाभ और आय वृद्धि के माध्यम से ₹28.37 ट्रिलियन शुद्ध कर प्राप्तियों (+11% YoY) पर बैंक	उच्च आय वालों (30% स्लैब अपरिवर्तित) या धन परिसंपत्तियों के लिए कोई प्रतिपूरक कर नहीं, जिससे ₹1.26 लाख करोड़ की कमी का जोखिम है
व्यय फोकस	बुनियादी ढांचे के गुणकों के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर ₹11.2 लाख करोड़ (+17.4% YoY) किया गया	सामाजिक क्षेत्र का आवंटन स्थिर बना हुआ है, वित्त वर्ष 2024 में संशोधित व्यय प्रारंभिक अनुमानों से 15% कम है।

आगे की राह:

- संतुलित राजकोषीय दृष्टिकोण - आक्रामक राजकोषीय संकुचन के बजाय, सरकार को घरेलू मांग और आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिए, विशेष रूप से बुनियादी ढांचे और सामाजिक क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक व्यय को बनाए रखते हुए, धीरे-धीरे घाटे में कमी की रणनीति अपनानी चाहिए।
- करदाताओं पर बोझ डाले बिना राजस्व बढ़ाना - डिजिटल ट्रैकिंग के माध्यम से कर अनुपालन को मजबूत करना, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और मध्यम वर्ग पर बोझ बढ़ाए बिना राजकोषीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए धन और उच्च आय वाले क्षेत्रों पर प्रगतिशील कराधान की संभावना तलाशना।

UPSC Mains PYQ : 2018

प्रश्न: 2018-2019 के केंद्रीय बजट में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर (एलसीजीटी) और लाभांश वितरण कर (डीडीटी) के संबंध में पेश किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर टिप्पणी करें।

GEO IAS
It's about quality

In News : Benets Accorded to Classical Language

2024 के केंद्रीय बजट में अगले पाँच वर्षों में चार करोड़ नौकरियाँ सृजित करने के प्रयास के तहत रोज़गार से जुड़े प्रोत्साहन (ELI) पेश किए गए हैं। हालाँकि, भारत को दीर्घकालिक आर्थिक विकास और वेतन स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार की नौकरियाँ सृजित करनी चाहिए, इस पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और विकसित हो रही युवा आकांक्षाओं द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के साथ।

जलवायु-लचीली नौकरियाँ

- जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: भारत जलवायु परिवर्तन के कारण अपार चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसने 2021 में $159 बिलियन का नुकसान उठाया है। 2030 तक, देश को जलवायु अनुकूलन के लिए लगभग 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की आवश्यकता होगी।
- ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन: सरकार को ऐसी नौकरियाँ सृजित करनी चाहिए जो जलवायु लचीलापन को बढ़ावा दें, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में ई-रिक्शा या ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और कार्बन पदचिह्नों को कम करने के लिए बायोगैस संयंत्र।
- हरित नौकरियों की संभावना: गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर ऊर्जा का विस्तार, लाखों नौकरियों का सृजन कर सकता है, विशेष रूप से छत पर सौर प्रतिष्ठानों जैसी विकेन्द्रीकृत ऊर्जा प्रणालियों में जो श्रम-गहन हैं।

रोजगार में एआई-लचीलापन

- एआई-संचालित नौकरी का नुकसान: जनरेटिव एआई और ऑटोमेशन का उदय आईटी और व्यावसायिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में नौकरी की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। मैकिन्से का अनुमान है कि भारत में 50% ऑटोमेशन अगले दशक में हो सकता है।
- एआई-लचीलापन नौकरियां: प्रभाव को कम करने के लिए, नई नौकरी सृजन को शारीरिक जुड़ाव और रचनात्मकता को प्राथमिकता देनी चाहिए, जैसे कि प्रतिभा की कमी को दूर करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों का विस्तार करना।
- ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाना: राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी पहलों को वित्तपोषित करने से ग्रामीण कारीगरों, किसानों और शिल्पकारों को वैश्विक और शहरी बाजारों में प्रवेश करने में मदद मिल सकती है, जिससे पारंपरिक क्षेत्रों के बाहर नौकरी सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

ग्रामीण युवाओं के लिए आकांक्षा-केंद्रित नौकरियां

- ग्रामीण युवाओं की चुनौतियाँ: स्टार्टअप में बढ़ती रुचि के बावजूद, ग्रामीण युवाओं को अक्सर खराब बुनियादी शिक्षा, कम संसाधनों और नौकरी के अवसरों की कमी से उपजी असुरक्षा का सामना करना पड़ता है।
- बुनियादी ढांचे के माध्यम से रोजगार सृजन: एकीकृत पैक-हाउस का निर्माण और ग्रामीण विनिर्माण को बढ़ावा देने से ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों नौकरियां मिल सकती हैं, बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा किया जा सकता है और आर्थिक स्थितियों में सुधार हो सकता है।

- आकांक्षापूर्ण रोजगार सृजन: राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन जैसी पहलों को आगे बढ़ाने के लिए निजी-सार्वजनिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने से आयात निर्भरता को कम करने और आकांक्षापूर्ण गैर-कृषि रोजगारों का सृजन करके ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने में मदद मिल सकती है।

UPSC Mains Practice Question

प्रश्न: भारत को दीर्घकालिक आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए तीन प्रकार की नौकरियों का सृजन करने की आवश्यकता है, इसकी आलोचनात्मक जांच करें। ये रोजगार सृजन रणनीतियाँ जलवायु परिवर्तन, एआई स्वचालन और ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं की चुनौतियों का समाधान करने में कैसे मदद कर सकती हैं? (250 Words /15 marks)

GEO IAS
It's about quality

GEO IAS
It's about quality

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

Page : 08 Editorial Analysis

The U.S.'s WHO exit, a chance to reshape global health

On January 20, 2025, the United States government issued an executive order to withdraw from membership of the World Health Organization (WHO). This has raised apprehensions that reduced funding for WHO would impact the functionality of the organisation. However, as the executive decision by the U.S. government has already been made, it is time to reflect on some fundamental questions such as why a single country's exit from WHO is causing so much concern. How can the U.S.'s exit from WHO be converted into an opportunity to create a stronger WHO? Why is there a need for an increasingly greater role of countries in Asia and Africa in global health.

Dr. Chandrakant Lahariya

is a medical doctor and a specialist in global health, with nearly 17 years of professional work experience with the United Nations system including the World Health Organization (WHO) and UNICEF

Funding intricacies

To understand the impact of the U.S.'s withdrawal on WHO funding, we need to understand WHO's funding system. There are two broad categories of funding sources. In the first, the assessed contribution (or AC) is a fixed amount each WHO member-state must pay annually as a sort of membership fee. This is what the U.S. President has argued as being disproportionately high (for the U.S.) and cited as one of the four reasons for the U.S.'s decision regarding its withdrawal. The assessed contributions ensure assured funding, which WHO uses to pay the salaries of regular staff, both technical and administrative, and maintain day-to-day functioning. This is the minimum resources the organisation needs to ensure a continuity of operations.

The other funding pool is from voluntary contributions (or VC) which comes from a range of donor agencies and additional contributions from WHO member-states. VCs are broadly for projects and other time-bound activities. WHO uses VC funds in the hiring of short-term staff and consultants. However, the problem with VC funds is that these are – as the name suggests – voluntary, always time-bound, linked to specific activities, and, thus, unpredictable.

For example, many member-states and donors provide funds for polio elimination, patient safety, primary health care or antimicrobial resistance-related work. These contributions are tight-jacketed and non-transferable to other activities. With the U.S.'s withdrawal from WHO, the VC would also be impacted, as many U.S.-based or U.S.-aligned donors may either reduce, or worse, completely stop the funding to WHO. As an example, the ongoing turmoil and uncertain fate of USAID would additionally impact WHO funding. Clearly, the financial impact on WHO is likely to be far greater than the direct share of the U.S. government funds for WHO.

Another argument given for the U.S.'s withdrawal, which has been used frequently by some others to criticise WHO, is that the organisation is highly bureaucratic, acts slow and is in need of urgent reforms. This is partially true and to be fair in assessment, every global institution needs some reforms and WHO is not any different. In fact, there is far more to WHO's credit than the occasional systemic blips it has faced. In this era of emerging and multi-sectoral challenges such as antimicrobial resistance, climate change, global warming and animal health, increasing re-emergence of diseases and a steep rise in lifestyle diseases, the world needs a stronger WHO, more than ever.

It is time for the countries in the global south to support WHO and initiate collaborative actions to reshape the global health agenda

Why institutions fail

In their book, *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, Daron Acemoglu and James A. Robinson (they were conferred the Nobel Prize in Economics in 2024) hypothesize, *inter alia*, that nations thrive upon the foundation and the strengths of functioning and stronger institutions.

Expanding the analogy at a global level, the world needs stronger institutions for peace and global health. However, in the last few decades, the fibres of global collaboration have been damaged. There is rising nationalism in many countries and 'Nation first' is becoming a vote-catcher for many leaders. This phenomenon of hyper-nationalism is global but relatively new, and, thus, arguably more virulent in high-income countries. Hyper-nationalism often undermines global institutions.

With the U.S.'s exit from WHO, the likelihood of key multi-country alliances such G-7, G-20 and others stepping in to support and fund WHO are feeble. Yet, for its tremendous body of work in the last 75 years, it is a moral imperative for all countries that the alternatives are explored to protect and save global institutions. The legitimate governments and elected political leaders in the global south and countries such as India, Brazil, South Africa, Thailand, Egypt and many others need to step up to support WHO in specific, and the United Nations in general.

There is another important consideration – the inexcusable gap in global health priorities and funding. The health challenges which affect the countries in Asia and Africa are grossly underfunded; mPox did not get global attention till it started affecting people in high-income countries in 2022. The vaccines and drugs against mPox are barely available in the Democratic Republic of the Congo and other settings where disease is most rampant but offered liberally in the U.S. which has a few mPox cases. This is a reminder that high-income countries continue to shape the policies, health agenda and command influence in global health, inadvertently widening health inequities. Global health has arguably been a case of 'He who pays the piper calls the tune'.

The decision to recall U.S. government personnel who have been seconded to WHO and subsequent apprehension that such a step would slow down ongoing programmes reflect how global health agencies are a little too dependent on subject experts originating from a single or select few countries. Global health will be better off if a pool of subject experts in various areas of public health are available from different countries and in the majority of the countries. There are a few things which should be considered immediately.

The global south must act

First, countries in the global south, especially Asia and Africa, must team up to supplement WHO funding gap after the U.S.'s exit. BRICS could be one such platform. Second, countries such as India, Ethiopia, Ghana, and others in the global south need to invest in training of experts not just in public health but also global health (these are different areas). For example, India should have trained experts in conditions which affect Africa and diseases which are not prevalent in our country. The era of providing only financial support to any country is behind us. It is time for 'pooled' technical expertise in health, as in any other sector). Third, the countries in the global south should set up a few premier institutions at the country or at regional levels through inter-country collaboration to train their experts in global health. It is the expertise from low- and middle-income countries which will be of help to each other and to WHO by the secondment of such experts. That way, global health can improve at a much lower cost than by expertise from high-income countries.

Fourth, we have been hearing of reforms in WHO for a long time. One of the steps which should be considered urgently is to trim staff and move the headquarters to one of the regional offices in Brazzaville (Congo), Cairo, Manila or New Delhi. This would reduce the headquarter's operational costs. Though this might be a problem in terms of air connectivity, the time and the focus of WHO's work needs to be on geographies where attention is needed: Africa and Asia. It would be a very strategic move to scale down the headquarters and move specific divisions to the regional offices.

It is very likely that four years later or some time in future, when there is a new U.S. President, the U.S. would rejoin WHO. However, till then, the U.S.'s withdrawal should be explored as an opportunity for the public health community and political leadership in the global south to initiate country and regional level and collaborative actions to reshape the global health agenda, which is much under the influence and the guidance of high-income countries. Global health should not be at the mercy of funding or the expertise from one or a handful of high-income countries. It must be truly a joint venture for the entire world, led by the global south.

The views expressed are personal

GS Paper 02 : अंतरराष्ट्रीय संबंध

PYQ (UPSC CSE (M) GS-2 2020): कोविड-19 महामारी के दौरान वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने में डब्ल्यूएचओ की भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें। (150 Words /10 marks)

संदर्भ:

- 20 जनवरी, 2025 को, संयुक्त राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से हटने के लिए एक कार्यकारी आदेश जारी किया, जिससे वैश्विक स्वास्थ्य निकाय की वित्तीय और परिचालन स्थिरता के बारे में गंभीर चिंताएँ पैदा हो गईं।
- जबकि इस निर्णय ने कम वित्त पोषण के कारण WHO के संभावित कमज़ोर होने के बारे में बहस छेड़ दी है, यह वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे को आकार देने में विभिन्न देशों की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रस्तुत करता है।
- इन घटनाक्रमों के बीच, अमेरिका के हटने के निहितार्थ, WHO के वित्त पोषण ढांचे द्वारा उत्पन्न चुनौतियों और वैश्विक स्वास्थ्य में वैश्विक दक्षिण की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता का पता लगाना महत्वपूर्ण है।

WHO की फंडिंग प्रणाली और अमेरिका के हटने के परिणाम

- **WHO की फंडिंग प्रणाली**
  - o WHO के वित्त पोषण को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है: मूल्यांकित योगदान (AC) और स्वैच्छिक योगदान (VC)।
  - o AC एक निश्चित वार्षिक सदस्यता शुल्क है जिसे प्रत्येक सदस्य-राज्य को भुगतान करना होता है, जो WHO के बुनियादी संचालन, जैसे वेतन और प्रशासनिक लागतों के लिए स्थिर वित्त पोषण सुनिश्चित करता है।
  - o अमेरिका द्वारा अपनी वापसी के लिए बताए गए प्रमुख कारणों में से एक यह था कि उसका AC अनुपातहीन रूप से उच्च था।
  - o दूसरी ओर, VC फंड, जो विभिन्न दाताओं से आते हैं और अक्सर विशिष्ट परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाते हैं, स्वाभाविक रूप से अप्रत्याशित होते हैं।
- **अमेरिका की वापसी के परिणाम**
  - o अमेरिका के बाहर निकलने से, न केवल उसके AC योगदान समाप्त हो जाएँगे, बल्कि उसका VC फंडिंग भी कम हो सकता है क्योंकि USAID जैसी अमेरिकी-आधारित दाता और एजेंसियाँ WHO को अपना फंडिंग कम या रोक सकती हैं।
  - o यह देखते हुए कि इनमें से कई फंड पोलियो उन्मूलन, रोगी सुरक्षा और रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं का समर्थन करते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य पहलों को निष्पादित करने की WHO की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।

- हालाँकि, वित्तीय झटका महत्वपूर्ण है, लेकिन यह WHO की फंडिंग संरचना की भेद्यता और सुधार की आवश्यकता को भी उजागर करता है।

वैश्विक संस्थाओं की विफलता के पीछे का कारण

- **राष्ट्रवाद का उदय और वैश्विक सहयोग पर इसका प्रभाव**
- हाल के वर्षों में, कई देशों में राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी है, जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कीमत पर घरेलू प्राथमिकताओं पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है।
- उच्च आय वाले देशों के राजनीतिक नेताओं ने अपने घरेलू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए 'राष्ट्र-प्रथम' नीतियों को तेजी से अपनाया है।
- इसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के लिए कम धन उपलब्ध हुआ है, गठबंधन कमजोर हुए हैं और बहुपक्षीय प्रयासों में शामिल होने में अनिच्छा हुई है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका का बाहर होना इस प्रवृत्ति का एक प्रमुख उदाहरण है।
- वित्तीय योगदान और नौकरशाही की अक्षमताओं पर चिंताओं का हवाला देते हुए, अमेरिकी सरकार ने एक ऐसे संगठन से बाहर निकलने का फैसला किया जो ऐतिहासिक रूप से स्वास्थ्य संकटों के लिए वैश्विक प्रतिक्रियाओं के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।
- यह निर्णय न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रभावी रूप से कार्य करने की क्षमता को कमजोर करता है, बल्कि अन्य देशों को यह परेशान करने वाला संकेत भी देता है कि राजनीतिक रूप से सुविधाजनक होने पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को छोड़ा जा सकता है।

वैश्विक संस्थाओं में विश्वास का क्षरण

- वैश्विक संस्थाओं के सामने एक और बड़ा मुद्दा सदस्य देशों के बीच विश्वास का क्षरण है।
- पिछले कुछ वर्षों में, कुछ देशों ने WHO जैसे संगठनों की धीमी गति से काम करने, अत्यधिक नौकरशाही और कुछ शक्तिशाली देशों के हितों से प्रभावित होने के लिए आलोचना की है।
- हालांकि ये आलोचनाएँ पूरी तरह से निराधार नहीं हैं, लेकिन इनके कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जहाँ देश वैश्विक पहलों का पूरा समर्थन करने में हिचकिचाते हैं, उन्हें डर है कि उनके हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं किया जाएगा।
- COVID-19 महामारी ने इनमें से कुछ कमियों को उजागर किया। वायरस को महामारी घोषित करने में देरी और कुछ सदस्य देशों से मिली जानकारी पर अत्यधिक निर्भरता के लिए WHO की आलोचना की गई।
- ये चिंताएँ, जबकि वैध हैं, वैश्विक संस्थाओं को पूरी तरह से त्यागने के बहाने के बजाय सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम करनी चाहिए।
- एक मजबूत WHO, जो अधिक पारदर्शी, कुशल और समान रूप से शासित हो, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है।

वैश्विक संस्थाओं में प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता

- **वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण**
  - o जिनेवा में WHO का मुख्यालय उन क्षेत्रों से बहुत दूर है, जो सबसे ज़्यादा दबाव वाली स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
  - o WHO के संचालन के कुछ हिस्सों को अफ्रीका या एशिया के क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थानांतरित करने से प्रतिक्रिया समय में सुधार हो सकता है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि संसाधनों को वहाँ निर्देशित किया जाए जहाँ उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

वित्त पोषण स्रोतों का विविधीकरण

- o किसी एक देश पर निर्भरता कम करने के लिए, WHO और इसी तरह की संस्थाओं को अपने वित्त पोषण तंत्र में विविधता लानी चाहिए।
- o कई देशों से सामूहिक योगदान को प्रोत्साहित करना, साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य बॉन्ड या सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे अभिनव वित्तपोषण तंत्र वित्तीय स्थिरता को बढ़ा सकते हैं।

- **निर्णय लेने में समावेशिता को बढ़ाना**
  - o ऐतिहासिक रूप से, वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों पर उच्च आय वाले देशों का वर्चस्व रहा है।
  - o यह सुनिश्चित करना कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ज़्यादा आवाज़ मिले, इससे ज़्यादा न्यायसंगत और प्रभावी नीतियाँ बनेंगी।
  - o विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व और शासी निकायों में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से प्रतिनिधित्व बढ़ाकर इसे हासिल किया जा सकता है।

प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना

- वर्तमान में, कई वैश्विक स्वास्थ्य समझौतों में प्रवर्तन तंत्र की कमी है, जिससे देशों को जवाबदेह ठहराना मुश्किल हो जाता है।
- गैर-अनुपालन के लिए दंड के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं को पेश करने से वैश्विक स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन बढ़ सकता है।

संस्थाओं को मजबूत करने में वैश्विक दक्षिण की भूमिका

- वैश्विक संस्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों के मद्देनजर, वैश्विक दक्षिण के देशों को अपने भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए।
- वैश्विक स्वास्थ्य एजेंडे को निर्धारित करने के लिए उच्च आय वाले देशों पर निर्भर रहने के बजाय, भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और थाईलैंड जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शासन में अग्रणी के रूप में आगे आना चाहिए।
- ब्रिक्स (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) जैसे संगठन डब्ल्यूएचओ की पहलों को वित्तपोषित करने और समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
  - o इसके अतिरिक्त, वैश्विक दक्षिण के भीतर वैश्विक स्वास्थ्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निवेश करने से विशेषज्ञों का एक अधिक विविध और आत्मनिर्भर पूल बनाने में मदद मिलेगी, जिससे पश्चिमी प्रशिक्षित पेशेवरों पर निर्भरता कम होगी।

- इसके अलावा, अफ्रीका और एशिया के देशों को अधिक निष्पक्ष वैश्विक स्वास्थ्य नीतियों की वकालत करनी चाहिए।
- सामूहिक रूप से डब्ल्यूएचओ और अन्य संस्थानों में सुधारों पर जोर देकर, वे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकताएँ सभी देशों की ज़रूरतों को प्रतिबिंबित करें, न कि केवल उच्च आय वाले देशों की।

निष्कर्ष

- जबकि डब्ल्यूएचओ से अमेरिका का बाहर निकलना तत्काल चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है, यह वैश्विक स्वास्थ्य शासन के पुनर्गठन का अवसर भी प्रदान करता है।
- यह निर्णय एक मजबूत डब्ल्यूएचओ की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो वित्त पोषण और विशेषज्ञता के लिए किसी एक देश पर कम निर्भर हो।
- वैश्विक दक्षिण के देशों को वित्तीय योगदान बढ़ाकर, अधिक विशेषज्ञों को प्रशिक्षित करके और वैश्विक स्वास्थ्य के लिए समर्पित क्षेत्रीय संस्थानों की स्थापना करके इस अंतर को भरने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
- अमेरिका के बाहर निकलने को संकट के रूप में नहीं बल्कि अधिक स्वतंत्र और लचीले डब्ल्यूएचओ के लिए उत्प्रेरक के रूप में देखा जाना चाहिए।

GEO IAS
It's about quality